

गौलना

फारम-23

परियोजना का नाम -

जनपद कलसी में देहात विरासी कोट का
का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गौलना
तहसील कलसी जिला अमरसिंह
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जलसंधारण में जनपद अमरसिंह के अन्तर्गत अमरसिंह कोट का परियोजना के निर्माण हेतु (
 हे० आरक्षित वन भूमि हे० सिविल सौजन्य भूमि 1.110 हे० वन पंचायत भूमि 3.313 हे०) अर्थात् कुल 4.523
हे० वन भूमि का को. नि. विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण को विषय में ग्राम पंचायत गौलना द्वारा दिनांक 10-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
तपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के तत्पश्चात् ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गौलना के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10-1-015 प्रयोज्य एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


ग्राम पंचायत अधिकारी / अधिकारी
मंत्र गौलना
को ख० स्थान (अमरसिंह)



गीलन।

प्राकप -25.1

दिनांक 10-1-05 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - गीलन।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित शरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मिलोक सिंह	मिलोक सिंह
2-	डविपानन्द मिश्रा	डविपानन्द
3-	हरी-दत्त	Haridutt
4-	दरवान सिंह	दरवान सिंह
5-	अश्वत सिंह	अश्वत सिंह
6-	नवीन-चन्द	Naveen chand
7-	अश्व-दत्त	अश्व-दत्त



परियोजना का नाम -

(जनपद अल्मोड़ा में देहार और सी मोटर मार्ग का निर्माण)

वन अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ज्वालविना

तहसील स्यौदी जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.11.0 हे० आवंटित वन भूमि 3.39.5 हे०) अर्थात् कुल 4.505 हे० वन भूमि का को. डि. विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ज्वालविना द्वारा दिनांक 10-1-015 को सम्मान ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ज्वालविना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को. डि. प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत के अध्यक्ष
ग्राम पंचायत
वि० ख० स्यान्दे (अल्मोड़ा)

Kaush
ग्राम प्रधान 5/7/016
ग्राम पंचायत स्वात्मवीणा
वि० ख० स्यान्दे (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 10.11.2013 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत 10.11.2013

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	दलीप सिंह पुत्र मोहन सिंह	दलीप सिंह
2-	दुगर राम पुत्र राम राम	दुगर राम
3-	खाली राम पुत्र डबर राम	Khayal Ram
4-	गोपाल सिंह पुत्र मोहन सिंह	गोपाल सिंह
5-	हरीश राम पुत्र दीवाना राम	Hari
6-	भवानी राम पुत्र उदी राम	Havan
7-	जीत सिंह पुत्र ह्यान सिंह	जीत सिंह
8-	नेहा सिंह पुत्र कैशर सिंह	नेहा सिंह

ग्राम प्रधान 5/11/13

ग्राम पंचायत गवालिविना
पि० ख० प्रमोद चंद आलोक

परियोजना का नाम :-

जलमय कलकटा में देवार गौरीसी कोटल जमीन का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पञ्चायत का नाम कलकटा-11

तहसील खाली

जिला अरमोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अरमोड़ा के अन्तर्गत अरमोड़ा मोटल जमीन परियोजना के निर्माण हेतु (4.515 हे० आरक्षित वन भूमि 4 हे० सिविल सौख्य भूमि 1.110 हे० वन पंचायत भूमि 3.395 हे०) अर्थात् कुल 4.515 हे० वन भूमि का को.रि. विभाग / संस्था के फल में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कलकटा-11 द्वारा दिनांक 10-1-03 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कलकटा-11 के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को.रि. वि. प्रयोज्य एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

वन पञ्चायत कलकटा-11 द्वारा
ग्राम पंचायत कलकटा-11 द्वारा
दि० १०/०१/०३ (अरमोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुखर सक्सेना

कामगाराना

प्राकृत - 25.1

दिनांक 10-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कामगाराना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित नरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	जेठलामिष्ट ड० शरामिष्ट	जेठलामिष्ट
	उमरावामिष्ट ड० हरामिष्ट	उमरावामिष्ट
	मिश्रामिष्ट ड० मोरामिष्ट	मिश्रामिष्ट
	बेचामिष्ट ड० मिश्रामिष्ट	बेचामिष्ट
	जयनामिष्ट ड० कल्याणामिष्ट	जयनामिष्ट
	उमरावामिष्ट ड० राजेश्वरामिष्ट	उमरावामिष्ट



पपड़िया

प्रारूप-23

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में वैदर गौदासी मोर
मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गौलना / पपड़िया
तहसील खसाम जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वैदर गौदासी मोर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (.....
हे० आवंटित वन भूमि हे० निवृत्त सोपन भूमि 1:100 हे० वन पंचायत भूमि 3:245 हे०) अर्थात् कुल 4:505
हे० वन भूमि का खोदे रोड विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापनित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गौलना द्वारा दिनांक 10-1-05 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पपड़िया
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि खोदे रोड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


ग्राम पंचायत सर्वशक्ति अधिकारी
पत्र गौलना
दिनांक 10-1-05



दिनांक 10-1-15 को ग्राम सभा की सम्मान बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मोहनपुर/प.प्र.डि.वा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दुर्गा देवी	दुर्गा देवी
	रघुनाथ सिंह	रघुनाथ सिंह
	शैलेश चन्द	कैलाश चन्द
	श्री वल्लभ	श्री वल्लभ
	वासुदेव चन्द	वासुदेव चन्द
	श्यामल देवी	श्यामल देवी
	नवीन चन्द	नवीन चन्द



चर्मा चौगा

प्रास-23

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में देहात जाहिराती
मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सनडमीडा / चर्मा चौगा
तहसील सुपौल जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत 3.45.1.19 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (
हे० आरक्षित वन भूमि हे० सिविल सौधम भूमि 1.48 हे० वन पंचायत भूमि 3.34.5 हे०) अर्थात् कुल 4.50.5
हे० वन भूमि का चर्मा चौगा विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रमाणित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सनडमीडा द्वारा दिनांक 10-1-05 को सम्मान ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रस्ताव एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
संप्रस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्मा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चर्मा के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि चर्मा चौगा प्रस्तावित एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत, सनडमीडा
चौगा चौगा, अल्मोड़ा


ग्राम पंचायत / सचिव
कान्ता कुमारी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सनडमीडा
चौगा चौगा, अल्मोड़ा

दिनांक 19-1-015 को ग्राम सभा की समीक्षा बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सन 2014-15 / चौना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विरे-साहू	विरे-साहू
2	आन-साहू	आन-साहू
3	भीमा-साहू	भीमा-साहू
4	लक्ष्मी-साहू	लक्ष्मी-साहू
5	कुमार राम	कुमार राम
6	मदन राम	मदन राम
7	कुशल राम	कुशल राम

ग्राम प्रधान/समिति
कान्ता देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सन 2014-15
वेत खा ग्यान्डे (अन्तर्गत)

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में डेढ़ाट जोरसी मोटर
मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सनडभीड़ा
तहसील स्याब जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत डेढ़ाट जोरसी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु
है० आवंटित वन भूमि ४ है० सिविल सोयम भूमि १.११० है० वन पंचायत भूमि ३.३९८ है० अर्थात् कुल ४.५०८
है० वन भूमि का जोरसी विभाग / संस्था के पास में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सनडभीड़ा द्वारा दिनांक १८-१-२०१८ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा उद्घट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हानन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धर्मो र्मोना के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जोरसी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत सनडभीड़ा
जिला अल्मोड़ा

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत सनडभीड़ा
जिला अल्मोड़ा

चमो चौमा

प्राकृत - 23.1

दिनांक 10-1-05 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सनडा भौडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगत सिंह उपाधिकारी	जगत सिंह
2	राजे सिंह उपाधिकारी	प्रेमसिंह
3	पुरनासिंह	पूरन सिंह
4	हबवान सिंह	रामान सिंह
5	गोविन्द राम	गोविन्द राम
1	रामासिंह	रामासिंह
7	सुधानासिंह	सुधानासिंह

ग्राम प्रधान (सरपंच)
कान्ती देवी
ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत सनडा भौडा
जिला राय बरेली (अलीगढ़)

दुवसील

ढा.रूप-23

परियोजना का नाम :-

जनपद अमरकोट के देहार गौरीसी मोटा
माड़ी का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम संचायक का नाम उपरी / दुवसील
तहसील सुपारी जिला अमरकोट
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अमरकोट के अन्तर्गत उपरी मोटा माड़ी परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....8 हे० आरक्षित वन भूमि 1480 हे० निषिद्ध संरक्षित भूमि 2500 हे० वन पंचायत भूमि 4505 हे०) अर्थात् कुल 4.505
हे० वन भूमि व को. नि. विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम संचायक उपरी द्वारा दिनांक 10-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम संचायक की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुवसील
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


ग्राम सचिव
वि० ख० म्यान्ने (अमरकोट)


सरपंच
वन अधिकार प्रमाण पत्र
पट्टी पर बनाया गया है
पि० देहाट (उत्तराखण्ड)

दुधमाल

प्रासप -25.1

दिनांक 10-1-013 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत उमराही / दुधमाल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	<u>नन्दन सिंह</u>	<u>नन्दन सिंह</u>
2	<u>खुशाल सिंह</u>	<u>खुशाल सिंह</u>
3	<u>गोपाल सिंह</u>	<u>गोपाल सिंह</u>
4	<u>दिनेश चन्द</u>	<u>दिनेश चन्द</u>
5	<u>नन्दन सिंह</u>	<u>नन्दन सिंह</u>
6	<u>बन्नी राम</u>	<u>बन्नी राम</u>
7	<u>नन्दन सिंह</u>	<u>नन्दन सिंह</u>

ग्राम प्रधान / सदस्य

[Signature]

बन नन्दन दुधमाल
गुड्डा पंचायत की सीट
पान रोड (गुड्डा)

सौ. गड

डाक्यू-23

परियोजना का नाम

जनपद अल्मोड़ा में देदार गौरासी मोरल मार्ग
का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

गाला न-1/सौ. गड

तहसील

स्यादे

जिला

अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा

के अन्तर्गत उपरोक्त मोरल मार्ग

परियोजना के निर्माण हेतु

का आवेदन का नम्बर

के विषय में संशय नम्बर

30 का प्रस्ताव नम्बर

है। अर्थात् कुल

है। वन भूमि को

विनाय / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापनित करने हेतु आवेदन

उत्तराखण्ड किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गाला न-1

द्वारा दिनांक 12-1-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक

में प्रयुक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संरक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार

अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं

किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हस्त नहीं हो रहा

है। उक्त वन भूमि को संरक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि ग्राम

सौ. गड

ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को संरक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु दिव्य अनेक धन अर्पित नहीं है।

ग्राम प्रधान 5/1/20

ग्राम पंचायत गाला न-1
वि. 30 स्यादे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सचिव
वन मंत्रालय

ग्राम पंचायत गाला न-1
ग्राम पंचायत सचिव
वि. 30 स्यादे (अल्मोड़ा)

बसो गाँव

दिनांक 10-1-015 को ग्राम समी की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ...
राजेश्वर / सिद्ध

क्रमांक	ग्राम समी में उपस्थित व्यक्ति की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेश्वर सिंह पुत्र कुंवर सिंह	राजेश्वर सिंह
2-	दयान सिंह पुत्र उमेश्वर सिंह	दयान सिंह
3-	मदन सिंह पुत्र जमान सिंह	मदन सिंह
4-	गिरीश चन्द्र पुत्र मुरलीधर	गिरीश चन्द्र
5-	मोहन चन्द्र पुत्र हरीदत्त	मोहन चन्द्र
6-	खिला देवी पत्नी नन्दन सिंह	खिला देवी
7-	कुन्दन सिंह पुत्र दयान सिंह	कुन्दन सिंह
8-	जानन सिंह पुत्र मोहन सिंह	जानन सिंह

Handwritten signature
ग्राम प्रधान 5/7/016
ग्राम पंचायत बालासागर
पिन 751001 (भारत)

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में देदार जोरामा मोटर मार्ग
का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उपरमोटी जिला अल्मोड़ा
तहसील समाल अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरमोटी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.11.12 हे० आरक्षित वन भूमि 1.11.12 हे० सिविल सोरम भूमि 3.29.5 हे०) अर्थात् कुल 4.50.5 हे० वन भूमि वर जो.प्र.दि. विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यागर्हित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उपरमोटी द्वारा दिनांक 10-1-12 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयुक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कगोठिया डीना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जो.प्र.दि. प्रयुक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

[Signature]
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत उपरमोटी
पिन कोड 247101

[Signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत उपरमोटी
पिन कोड 247101
महेश साहू

पट्टी

प्राप्त - 25.1

दिनांक 10-1-20/5 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत (पट्टी) व.प्र.प्रधान

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अनन्दा सिंह	अनन्दा सिंह
2	कुशाल सिंह	कुशाल सिंह
3	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
4	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह (नन्दन सिंह)
5	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
6	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
7	अमदीश पाल सिंह	अमदीश पाल सिंह

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत पट्टी

दिनांक 10-1-20/5 (पट्टी) ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जंगल - कर्मोश में देघार - जौ रासी चौर
21/1

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जिला जंगल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र स्वावेद
उपखण्ड स्तरीय समिति, स्वावेद

उपखण्ड स्वावेद परिक्षेत्र के अन्तर्गत देघार - जौ रासी चौर
जंगल (4 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.11 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.32 हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.505 हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्वावेद) की दिनांक 10-12-2018 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री एन.एस.नरसिम्हा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री एन.एस.नरसिम्हा उप जिलाधिकारी एन.एस.नरसिम्हा अध्यक्ष
- 2- श्री वी.के.वि.ए. उप प्रभागीय वनाधिकारी राजेश सदस्य
- 3- श्री एन.के.वि.ए. सहायक समाज कल्याण अधिकारी एन.के.वि.ए. सदस्य/सचिव
- 4- श्री म.के.देवी बी०डी०सी० क्षेत्र म.के.देवी सदस्य

म.के.देवी
बी०डी०सी० क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि देघार - जौ रासी चौर जंगल

परियोजना 4.505 हे० वन
भूमि जंगल निगीर विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राजेश द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्योले परिक्षेत्र के अन्तर्गत
देवार जोरारी केरु चारा परियोजना के निर्माण हेतु
 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सखाम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
 प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी, स्योले
 उपखण्ड सतीचण्ड अधिकार सचि
 तहसील- स्योले
 जनपद- हावेली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी, स्योले
 उपखण्ड सतीचण्ड अधिकार सचि
 तहसील- स्योले
 जनपद- हावेली

प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में देघाट-जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा


जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा,
उत्तरांचल

1.6 g

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....1.6.01.15.....at time...6:00 PM.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring 4.505 hect. for the Construction of Deghat - Jaorasi meter Road..... of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


जिला अधिकारी
Signature
अल्मोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4,505het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above


 जिला अधिकारी
 अरमोड़ा
 Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

161

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudrapur

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 1.505 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept, Uttarakhand, (Name of user agency) for Construction of Dighat - Jorasi motor Road

(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Sunbura village(s) in Syalde Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.505 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above


जिला अधिकारी
 Signature
 (Full name of the official seal of the District Collector)